महत्तवपूर्ण/समयबद्ध संख्या /13-xix-2/02 मु0मं0घो०/2011

प्रेषक,

सुबर्द्धन, सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें.

आयुक्त,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः (फरवरी, 2013

विषयः उत्तराखण्ड राज्य के ए०पी०एल० श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 10 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रतिराशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 50,000 मी०टन चावल का अतिरिक्त MSP derived दरों पर अतिरिक्त आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।

महोदय.

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं० 02/Uttarakhand/2012-BP-III pt दिनांक 05.02.2013 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार द्वारा राज्य के ए०पी०एल० परिवारों के लिए मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत MSP derived दरों

पर 50,000 मी०टन चावल का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है।

उक्त के सम्बन्ध में शासन्भिविचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार से प्राप्त 50,000 मी०टन चावल का वितरण पूर्व से मिल रहे चावल के नियमित आवंटन को जोड़ते हुये 10 कि0ग्रा0 प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह के स्केल से ए०पी०एल० राशन कार्ड धारकों को शासनादेश सं० 60/12-xix-2/01 खाद्य/2010 दिनांक 27.01.2011 में उल्लिखित ₹ 6.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के सम्बन्ध में आवंटित 50,000 मी०टन चावल का उठान एवं लागत मूल्य का भुगतान पत्र जारी होने की तिथि से 50 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में करना सुनिश्चित करें।

संलग्क-यथोक्त

(सुबर्द्धन), सचिव।

संख्या १९६ (i) / 13-XIX-2 / 02 मु0मं0घो० / 2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।

- 2- निजी सचिव, मा० विभागीय मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
- 3- मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
- 4- आयुक्त गढघाल / कुमायू मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमायूँ सम्भाग / गढ़वाल सम्भाग, हल्द्वानी / देहरादून।
- 7- वित्त नियंत्रक अधिकारी, आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
- 8- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9— निदेशक, एन0आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 10- गार्ड फाईल।

आजा से (सुबर्ख न) सचिव

ON, letter 2011